[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

है हमारी स्थिति को महसूस किया है ! यही स्थिति है। मेरी बात पूरी हुई।

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं उत्तर नहीं दे रही हूं। विदेश मन्त्री बहस का उत्तर दे चुके हैं। मैं सदन को कुछ जानकारी मात्र देना चाहती हूं।

इस सदन तथा दूसरे सदन में हुई बहस में श्रीलंका की घटनाओं पर सारे देश में व्यक्त की गई चिंता की गंभीरता तथा व्यापकता पर पूरा बल दिया गया हैं।

मैं थोड़ी देर के लिए इस विषय से हटकर कुछ कहना और सदन को यह याद दिलाना चाहूंगी कि जब हम भारत के सर्वाधिक दूर दक्षिणी बिन्दु की चर्चा करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि पूर्व में निकोबार तथा पश्चिम में मिनिकाय कन्याकुमारी से भी अधिक दूर दक्षिण में है। मैं विशेषरूप से इसका उल्लेख इसलिए कर रही हूं क्योंकि जब भी मैं वहां गई हूं वहां के लोगों ने शिकायत की है और पूछा है कि क्या हम भारत का हिस्सा नहीं हैं। मुख्य भूमि के लोग कन्याकुमारी तक ही क्यों रुक जाते हैं ?" इसीलिए मैं चाहूंगी कि माननीय सदस्य इस बात को ध्यान में रखें।

अब जहां तक बहस की बात है इससे यह पता चलता है कि इन घटनाओं का सम्बन्ध केवल हमारी तमिल जनता से ही नहीं है बल्कि इससे सारे देश में क्षोभ व चिन्ता उत्पन्न हुई। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि कोलम्बो में हमले केवल तमिल लोगों पर ही नहीं हुए हैं। दो या तीन दिन पूर्व कुछ सिन्धी लोग मुझसे मिलने आए थे तथा वहां के उन कुछ सिंधियों का संदेश अपने साथ लाए थे जिनका सब कुछ लुट चुका है और जैसा कि मुझे बताया गया उनमें से कुछ तो श्रीलंका में 60 वर्ष या इससे भी अधिक अर्से से रह रहे थे। मुझे विश्वास है कि भारतीय मूल के अन्य लोगों को भी कष्ट उठाना पड़ा है।

महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि इस बहस में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों ने कुल मिलाकर संतुलन तथा संयम का परिचय दिया। जैसा कि विदेश मंत्री जी ने आपको अभी-अभी बताया अन्य देशों ने भी हमारे संयम की सराहना की है और इस विषय से हमारे विशेष विशेष सम्बन्ध को स्वीकार किया है। सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देती हूं।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि जब मैंने पिछले शुक्रवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति से टेलीफोन पर बात की थी तब उन्हें मैंने इस देश की चिन्ता से व्यक्तिगत रूप से अवगत कराया था। हमारे विदेश मंत्री जब कोलम्बो गए तो इस चिंता फिर दुहराया गया। वे संसद को इसके बारे में पहले ही जानकारी दे चुके हैं। राष्ट्रपति जयवर्धने ने मुझसे टेलीफोन पर बात की। उन्होंने मुझे बताया कि स्थिति नियंत्रण में आ रही है और हमारे लोग शीघ्र लोग ही अपने घरों को लौटने लगेंगे।

जैसा कि आप जानते हैं हमने प्रत्येक अवसर पर तथा हर संभव तरीके से यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत की ओर से श्रीलंका को कोई खतरा नहीं है और न ही हम उनके अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप ही करना चाहते हैं। मैंने राष्ट्रपति महोदय को इस बारे में पुन: आश्वासन दिया। हम चाहते हैं कि श्रीलंका की एकता तथा राष्ट्रीय अखण्डता बनी रहे। इसी के साथ ही साथ मैंने राष्ट्रपति महोदय को बताया कि श्रीलंका में होने वाली घटनाओं का असर हम पर भी पड़ता है। इस मामले में भारत को किसी अन्य देश के रूप में नहीं देखा जा सकता है। श्रीलंका और भारत दो ऐसे देश हैं जिनका इससे सीधा सम्बन्ध है। किसी बाह्य हस्तक्षेप से यह मामला दोनों देशों के लिए पेचीदा हो जाएगा। हम एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पर अनेक शक्तियों सक्रिय हैं जिनमें से कुछ भारत या हमारे पड़ोसियों का भला नहीं चाहती हैं। अस्थिरता पैदा करने वाली ताकतें सक्रिय हैं। अत: हमें हर ऐसा प्रयास करना है जिससे विदेशी तत्वों को हमें कमजोर बनाने का मौका कम से कम मिल सके।

ऐसी स्थिति में अन्य देशों की सरकारों द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की संभावना के बारे में सदस्यों की चिन्ता स्वाभाविक ही है। मैंने राष्ट्रपति से इस आशय की खबरों के बारे में पूछताछ की कि श्री लंका ने अन्य सरकारों से सम्पर्क किया है। उनका जवाब यह था कि अमरीका ने कुछ गेहूं तथा ब्रिटेन ने कुछ धन देने का वचन दिया है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : उनसे मांग की जाते पर या अपने आप ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जब मांग की गई। मैंने यह पूछा तो नहीं था बल्कि अन्य रिपोर्टों से अंदाजा लगाया है। राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि श्रीलंका में हमारे द्वारा भेजे गए जहाजों के अलावा अन्य कोई बाहरी जहाज नहीं हैं और उन्हें इस समय धन की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति महोदय के अनुसार, पुनर्वास का कार्य आरम्भ हो गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने इस कार्य के लिए एक विशेष प्राधिकारी नियुक्त किया हैं। राष्ट्रपति महोदय ने बताया कि लगभग 80,000 लोग विस्थापित हैं और उन्हें आशा हैं कि वे एक सप्ताह के भीतर अपने घरों को लौट जाएंगे। मैंने अपनी बातचीत के दौरान, पृथकतावादी आंदोलन तथा लोगों से निपटने के लिए श्रीलंक की सरकार द्वारा अपनाई गई विशेष शक्तियों की भी चर्चा की।

कुछ विशेष परिस्थितियों में यहां आवश्यक हो सकता है। फिर भी, उस देश तथा उससे बाहर होने वाली संभावित प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए, इस बात का काफी महत्व है कि इन शक्तियों का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। मैंने राष्ट्रपति महोदय को यह सुझाव दिया कि समाधान की प्रक्रिया शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ किए जाने के लिए हर सम्भव कदम उठाए जाने चाहिए। मैं इस स्थिति के विभिन्न पहलुओं या इसमें निहित खतरों पर नहीं जाना चाहती जो कि इस सम्बन्ध में बोलने वाले सदस्यों ने सामने रखे हैं। हम उनके प्रति सचेत हैं। इस समय हमारी रुचि दो बातों में हैं—एक तो यह कि मार-काट, तहस-नहस, लूटमार, और लोगों को सताया

[श्रीमती इन्दिरा गांधी]

आवश्यकता किया जाए तथा दूसरे, उन लोगों को जितनी सहायता हम दे सकते हैं दें जिन्हें इसकी जाना बन्द है । धन्यवाद

अध्यक्ष महोदय : 8 अगस्त, 1983 को 11 बजे म० प्र० को पुन: समवेत होने तक के लिए

8.58 म० प्र०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 8 अगस्त 1983/17 श्रावण, 1905 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

मुद्रक : आकाशदीप प्रिंटर्स, अनसारी रोड़, 20, दरियागंज, दिल्ली-110002